गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 075
दि. 14.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सेल्फी विद डॉटर' की जन्मस्थली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, 10 बार कर चुके हैं अभियान का जिक्र

(जीएनएस)।

17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जींद दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि जिले के लिए एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पल भी लेकर आएगा। प्रधानमंत्री 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान का जिक्र करने के बाद पहली बार उस धरती पर कदम रखेंगे, जहां से 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान की शुरूआत हुई थी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने संबोधनों और कार्यक्रमों में इस अभियान का अब तक 10 बार जिक्र कर चुके हैं।

जींद के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच एवं 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान के संस्थापक सुनील जागलान और उनके परिवार में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। उनके लिए यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं, बल्कि उस अभियान की स्वीकार्यता का प्रतीक है, जिसने बेटियों के सम्मान और संरक्षण का संदेश देश-दुनिया तक पहुंचाया।

सुनील जागलान का कहना है कि जिस धरती से बेटी बचाने के इस वैश्विक अभियान की शुरूआत हुई, उस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनी जुबां से 10 बार इस अभियान का जिक्र करना उनके लिए तो खास गर्व की बात है ही, लेकिन उससे भी बड़ा गर्व पूरे जींद जिले का है, क्योंकि इस अभियान ने जींद की पहचान देश और दुनिया तक पहुंचाई।

पीएम के जींद दौरे से पहले सामने आई सकारात्मक तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी के जींद दौरे से पहले जिले के लिए एक और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जींद के लिंगानुपात ने ऊंची छलांग पीएम के दौरे से पहले लगाई है। कुछ महीने पहले तक जिले का लिंगानुपात 900 के आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जून महीने में इसने बड़ी छलांग लगाई और यह बढ़कर 970 तक पहुंच गया। ऐसे समय में, जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ

के संदेश से जुड़े अभियान की जन्मस्थली पर आ रहे हैं, जिले के लिंगानुपात में आया यह सुधार भी एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदर्भ बन गया है।

10 बार प्रधानमंत्री की जुबां पर आया 'सेल्फी विद डॉटर'

जींद के बीबीपुर गांव से पूर्व सरपंच सुनील जागलान के सेल्फी विद डॉटर' अभियान को राष्ट्रीय पहचान तब मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और संबोधनों में इसका उल्लेख करना शुरू किया। अब तक प्रधानमंत्री इस अभियान का 10 बार जिक्र कर चुके हैं। हर बार उन्होंने बेटियों के सम्मान और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की सराहना की। अब उसी अभियान की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री का पहुंचना इस पहल के लिए एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम मोदी के स्वागत में दुल्हन की तरह सज रहा जींद, तैयारियों का जायजा लेने दूसरी बार पहुंचे सीएम नायब सैनी

(जीएनएस)।

जींद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार शाम को जींद का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पहले एकलव्य स्टेडियम के सामने हुडा ग्राउंड में रैली स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल के नक्शे का अवलोकन किया और मुख्य पंडाल, सेक्टर व्यवस्था, पार्किंग स्थल, मीडिया लाउंज, सुरक्षा प्रबंधों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। प्रधानमंत्री जींद की धरती से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा और देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

प्रधानमंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बैठक में यातायात व्यवस्था,

सीएनजी बसों व इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता, पार्किंग प्रबंधन और लोगों के आवागमन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार भाजपा नेता व मंत्री जींद का दौरा कर रहे हैं।

ये मुख्यमंत्री का एक सप्ताह के अंदर दूसरा दौरा था। वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने शनिवार देर शाम को रैली स्थल का दौरा किया था। रविवार दोपहर को भाजपा राष्ट्रीय ओमप्रकाश धनखड़ भी जींद पहुंचे। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश की ग्रीन एनर्जी यात्रा को हाइड्रोजन ट्रेन नई गति देगी।

प्रधानमंत्री हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने जींद आ रहे हैं। ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए आनंद का पर्व है। साथ ही ट्रेन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। ट्रेन सुबह 7:40 बजे जींद से चलकर 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में सोनीपत से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी। हालांकि, अभी किराये को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

रैली का नाम- विकसित हरियाणा, विकसित भारत

भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री की रैली को विकसित हरियाणा विकसित भारत नाम दिया गया है। इस रैली में रेल मंत्री के साथ और भी केंद्रीय मंत्री पहुंचने की संभावना है। रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा व प्रदेश सरकार किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती।

वॉटरप्रूफ टेंट, 10 हजार कुर्सियां लगेंगी

रैली स्थल पर लोगों के बैठने के लिए 10 हजार कुर्सियां लगाई जाएंगी। मुख्य स्टेज 96 फीट लंबा व 36 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। वीवीआईपी, वीआइपी के लिए अलग स्टेज बनाए जाएंगे। वीवीआईपी व वीआइपी के बैठने के लिए सोफे लगाए जाएंगे।

वर्षा होने पर किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए पूरा टेंट वॉटरप्रूफ होगा। रैली स्थल से एसपी कोठी तक खस्ताहाल सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का रैली स्थल पर पहुंचने का संभावित रूट है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का नितिन गडकरी, सीएम योगी और राजनाथ ने किया उद्घाटन, 30 मिनट में पूरा होगा 63 किमी. का सफर

(जीएनएस)।

उन्नावः उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का सोमवार को औपचारिक लोकार्पण हो गया है। उन्नाव के पड़री स्थित झाऊखेड़ा रेस्ट एरिया में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लोकार्पण के साथ ही यह हाईस्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल गया है।

इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। बता दें कि अभी ढाई से तीन घंटे लखनऊ से कानपुर सफर पूरा करने में लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ ये सफर महज 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है।

उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि जब सड़कें बेहतर होती

हैं, तब दूरी घटने के साथ-साथ विकास की गति बढ़ती है, निवेश के नए द्वार खुलते हैं और जनजीवन में नई संभावनाओं का संचार होता है। इसी विचार को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कर कमलों द्वारा आज 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास होगा। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, सुगम आवागमन और तीव्र आर्थिक प्रगति के नए अध्याय की आधारशिला सिद्ध होंगी।

कार्यक्रम के अनुसार, उन्नाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना होंगे। इसके बाद सरोजनीनगर में आयोजित मुख्य समारोह में परियोजना का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा।

इस दौरान तीनों नेता भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

उद्धव की पार्टी शिवसेना के 15 विधायक बदलेंगे पाला? मोदी के मंत्री का दावा, शरद पवार के खेमे में भी खलबली

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी (UBT) के विधायक दल में तीसरी बार बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार दावा किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया है।

आठवले के मुताबिक उद्धव ठाकरे के साथ बचे मुट्ठी भर विधायकों में से एक बड़ा ग्रुप बहुत जल्द उनका साथ छोड़ सकता है। इस खबर के बाहर आते ही न सिर्फ ठाकरे गुट बल्कि शरद पवार की पार्टी (NCP SCP) के अंदर भी भारी घबराहट देखी जा रही है।

टीवी9 मराठी समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि उद्धव ठाकरे गुट के 14 से 15 विधायक इस समय टूटने की कगार पर हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल जो 20 विधायक बचे हैं, उनमें से 14-15 विधायक पाला बदल सकते हैं।

आठवले ने यह भी संकेत दिया कि अगर ये नेता महायुति (बीजेपी-शिंदे-अजीत पवार गठबंधन) में शामिल होना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत करके उनका

स्वागत किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी किसी भी विधायक के नाम या तारीख का खुलासा नहीं किया है।

अगर 15 विधायक टूटे, तो उद्धव ठाकरे के पास कितने बचेंगे?

आइए अब उस गणित को समझते हैं जो इस समय उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाए हुए है। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो, उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल विधायकों की संख्या 20 है। टूटने की आशंका वाले विधायकों की संख्या 14 से 15 है। अगर यह दावा सच साबित होता है, तो उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 5 से 6 विधायक ही रह जाएंगे।

यह शिवसेना यूबीटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इससे पहले उनके सांसद और विधान परिषद (MLC) के कई बड़े चेहरे पहले ही एकनाथ शिंदे का दामन थाम चुके हैं।

दलबदल कानून से बचने के लिए एकनाथ शिंदे का 'सुपर 15' प्लान

इस पूरे खेल के पीछे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी की एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। सूत्रों की मानें तो शिंदे गुट पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे के करीब 10 विधायकों के साथ लगातार सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा था। ये 10 विधायक पाला बदलने के लिए लगभग राजी हो चुके हैं।

लेकिन कहानी में एक कानूनी पेंच है। दलबदल विरोधी कानून की कार्रवाई से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को उद्धव गुट के कम से कम दो-तिहाई विधायकों की जरूरत होगी। इसी वजह से शिंदे गुट अब 5 और विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है।

अब आसमान से निहारें बिहार की खूबसूरती, आज से हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू, सरकार दे रही सब्सिडी

(जीएनएस)।

बिहार घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का नजारा आसमान से देखने का सपना पूरा होने जा रहा है। बिहार सरकार ने हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरूआत कर दी है। 13 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि 18 जुलाई से नियमित उड़ानें शुरू होंगी।

पहले चरण में पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। सरकार यात्रियों को हर टिकट पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे कम खर्च में हवाई सफर और पर्यटन का आनंद लिया जा सकेगा।

हेली-टूरिज्म योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण का वाल्मीकिनगर, नालंदा का राजगीर और कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है। पटना से इन तीनों जगहों के लिए हर शनिवार और रविवार हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित होंगी। वाल्मीकिनगर के लिए राजकीय विमान का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि राजगीर और कैमूर के लिए 6+2 सीटर हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक उड़ान में पांच सीटें पर्यटकों के

लिए आरक्षित होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार यात्रियों को प्रति टिकट बड़ी सब्सिडी दे रही है। पटना से राजगीर का किराया 4,000 रुपये, वाल्मीकिनगर का 5,000 रुपये और कैमूर का 6,000 रुपये तय किया गया है। जबकि एक सीट की वास्तविक लागत करीब 17,522 रुपये है। बाकी राशि सरकार वहन करेगी। इससे आम लोगों को भी कम खर्च में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का हवाई सफर करने का मौका मिलेगा।

पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का भी मिलेगा रोमांच

पर्यटकों के लिए पटना शहर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की भी शुरूआत की जा रही है। इस सेवा के तहत लोग 10 मिनट तक आसमान से पटना का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। इसका किराया 2,100 रुपये प्रति सीट रखा गया है। इस सेवा पर भी सरकार प्रति सीट करीब 15,422 रुपये की सब्सिडी दे रही है।

'शीश झुकाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा', मंच पर रो पड़े नरोत्तम

मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही रस्साकसी का आज उस वक्त पटाक्षेप हो गया जब टिकट कटने के बाद खुद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके हिस्से का टिकट ले गए आशुतोष तिवारी का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे।

इस दौरान उनके साथ सूबे मुखिया मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी साथ रहे। 3 दिन से दतिया जिले में कट रहे गदर के बाद नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई अपने समर्थकों को संबोधित करने की।

56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय दल को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय दल को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (आईपीएचओ) 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल को बधाई दी है। उन्होंने कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी की उपलब्धि को देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उनकी सफलता की सराहना की।

युवा शक्ति और वैज्ञानिक सोच की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की यह उपलब्धि देश की युवा शक्ति की असीमित क्षमता तथा विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति उनके समर्पण और जुनून का एक और उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि ऐसे युवा देश के वैज्ञानिक भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।

पिछले दशक के प्रदर्शन का भी किया उल्लेख

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विभिन्न संस्करणों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए प्रेरणादायक बताते हुए विजेता छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

एक्स पर दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ह्लहमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन!' उन्होंने 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता युवा शक्ति की असीमित क्षमता और विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति उनके जुनून का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारतीय छात्रों ने इस मंच पर लगातार असाधारण प्रदर्शन किया है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

जे एण्ड के में स्टेटहुड पाने के लिये बड़े प्रदर्शन की कोशिशें

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जंतर-मंतर पर अलगाववादियों को निमंत्रणः पाकिस्तान समर्थक तत्वों का क्या उद्देश्य? उमर अब्दुल्ला ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली के लिए एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। इस प्रदर्शन में न केवल इंडिया गठबंधन के सहयोगी बल्कि जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक सहित 52 नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिहाज से गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या यह स्टेटहुड की मांग का बहाना है या पाकिस्तान समर्थक तत्वों को मुख्यधारा में लाकर भारत विरोधी एजेंडे को मजबूत करने की चाल? राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसी) के इस कदम ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एनडीए से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर सभी दलों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें मीरवाइज जैसे अलगाववादी भी शामिल हैं। मीरवाइज उमर फारूक लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफदारी के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दिए हैं और अलगाववादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जंतर-मंतर जैसे प्रतीकात्मक लोकतांत्रिक मंच पर आमंत्रित करना न केवल लोकतंत्र का दुरुपयोग है, बल्कि उन शक्तियों को बल प्रदान करना है जो भारत की एकता को चुनौती देते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और खतराः कश्मीर का इतिहास गवाह है कि अलगाववाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हजारों निर्दोष भारतीयों की जान ली है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में शांति और विकास की नई लहर आई है। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, पर्यटन बढ़ा, और युवा मुख्यधारा की राजनीति और अर्थव्यवस्था की ओर मुड़े। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, जिनकी पाटा ने कभी पाकिस्तान परस्त तत्वों से समझौते किए, अब फिर उसी पुरानी राह पर लौट रहे लगते हैं। मीरवाइज का निमंत्रण स्वीकार करना और उन्हें मंच देना यह संदेश देता है कि भारत सरकार की नीतियों के बावजूद अलगाववादियों को वैधता दी जा रही है। क्या इसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है या पाकिस्तान की आईएसआई को खुश करना? जंतर-मंतर पर यह प्रदर्शन न केवल स्टेटहुड की मांग करेगा, बल्कि संभवतः अनुच्छेद 370 की बहाली और विशेष दर्जे जैसे मुद्दों को भी उठाएगा, जो देश की अखंडता के लिए हानिकारक हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला की ओर से निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।

इसमें सोनिया गांधी, आसादुद्दीन ओवैसी, मायावती, अरविंद केजरीवाल की आप, अकाली दल आदि शामिल हैं। लेकिन मीरवाइज जैसे व्यक्ति का शामिल होना इस पूरे आयोजन को संदिग्ध बनाता है। मीरवाइज ने जंतर-मंतर प्रदर्शन का समर्थन करते हुए व्यापक जम्मू-कश्मीर अधिकार एजेंडे की बात कही है, जो स्पष्ट रूप से भारत विरोधी ताकतों का हिस्सा है।

राजनीतिक मकसद और जनता पर प्रभावः यह निमंत्रण उमर अब्दुल्ला की राजनीति की असफलता को भी उजागर करता है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद एनसी को सत्ता मिली, लेकिन स्टेटहुड की बहाली अभी लंबित है। इसके बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय वे पुरानी अलगाववादी राजनीति को पुनजावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करके वे संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र को घेरना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान समर्थक तत्व इस प्रदर्शन से क्या साबित करेंगे? वे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर अपनी पाकपरस्ती को वैधता देंगे। यह भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करेगा और कश्मीर में शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। घाटी के युवा, जो अब शिक्षा, रोजगार और पर्यटन से जुड़ रहे हैं, फिर से भटक सकते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टेटहुड बहाल की जाएगी, लेकिन सुरक्षा और विकास के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर में अभूतपूर्व विकास किया है- सड़कें, बिजली, इंटरनेट, पर्यटन।

प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कारों पर गार्जियन की हताशा

(जीएनएस)। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है।

दा गार्जियन अखबार ने मोदी और भारत की छवि धूमिल करने के लिए एक अंग्रेजी मे एक लेख लिखा। जिसका सारांश यह है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब यह अखबार कहना चाह रहा कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं, साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है, जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को इन देशों ने फिजूल में पुरस्कार दिए हैं। गार्जियन ने यह लेख लिख कर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ मोदी को पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कारों और उन देशों के राष्ट्रप्रमुखों का भी अपमान किया है।

इस लेख की भड़ास के बावजूद पीएम मोदी को पुरस्कारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से ऐसे 34 सम्मान मिल चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में सबसे अधिक हैं। इनमें से कुछ सम्मान सदियों पुराने हैं, जबकि कुछ सम्मान संबंधित देशों की सम्मान प्रणाली में हाल ही में शामिल किए गए हैं।

गार्जियन का यह लेख में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। विश्व का बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है, पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाड़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके बड़े उदाहरण हैं। जो विकसित देश भी हासिल नहीं कर सके। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनियां में हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत ने ही कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेज कर करोड़ों लोगों की जाने बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें विदेशी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता।

गार्जियन ने इसका जिक्र कभी नही किया कि विश्व को मोदी नेतृत्व में भारत ने क्या–क्या दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस ने अपना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन धरोहर योग को मोदी सरकार के प्रयासों से वैश्विक मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।

भारत ने प्राकृतिक आपदा के दौरान विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है। तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान'मिशन सागर'और'ऑपरेशन दोस्त'के जरिए विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्टाद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा (2025) और ऑपरेशन सहायता (2008) के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएँ दी गईं। श्रीलंका में सुनामी (2004) में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात (2025) में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

सरकारीएजेंसियां

भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है। इन अभियानों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के, पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है।

गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेज शासकों ने इस अवधि में भारतीयों पर अत्याचारों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। अंग्रेज व्यापारी बन कर आए और तानाशाह बन बैठे, खूब लूट खसौट की और भारत से सारा मालमत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है, जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था। भौगोलिकसंदर्भ

गार्जियन को यह कभी दिखाई नहीं दिया कि किस तरह केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भलाई का एक ऐतिहासिक काम किया, जिसे करने से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डरते रहे। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मिलने वाला कानून हक दिलवाया है। जिन्हें पहले पति तीन बार तलाक तलाक बोल कर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था।कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट के शाह बानों के फैसले को ही पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, इसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून बना दिया था।

विदेशी अखबारों को तकलीफ हो रही है कि मोदी राज में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जब भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तब खीझ उतारने के लिए कह दिया कि मोदी पुरस्कार के लिए दौड़े चले आते हैं। जिला स्तर, वार्ड स्तर, राज्यस्तर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्हें पाने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं। उसमें भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, तब कहीं जाकर किसी एक का चयन किया जाता है।

ऐसे में देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार का मापदंड कितने कठोर होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इन पुरस्कारों में पुरस्कार देने वाली सरकार के साथ उन देशों के करोड़ों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। चलो मान भी लिया जाए कि किसी एक देश ने भारत से कुछ फायदा लेने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया होगा, पर मोदी को तो दर्जनों देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, तो क्या इन सब देशों को मोदी फायदा पहुंचाएंगी, वो भी सिर्फ एक पुरस्कार के कारण, यदि ऐसा हुआ होता ना तो अब तक देश में तूफान आ जाता, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया होता। गार्जियन का यह लेख सिर्फ हताशा ही प्रकट करता है, इससे पहले भी इसी तरह के विदेशी अखबारों में लेखों के जरिए भारत की छवि और विकास की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने का असफल प्रयास किया जाता रहा है।

रक्षा सचिव और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री ने टोक्यो में आयोजित 8वें भारत-जापान रक्षा नीति संवाद की सह-अध्यक्षता की

भारत-जापान ने एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई

(जीएनएस)। भारत और जापान ने 13 जुलाई 2026 को जापान के टोक्यो में 8वें रक्षा नीति संवाद का आयोजन किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने किया और जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री श्री कानो कोजी ने किया। दोनों पक्षों ने पिछले रक्षा नीति वार्ता सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिवेश पर व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस संवाद में द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की गई, जिसमें सैन्य आदान-प्रदान, संयुक्त मुख्यालयों के बीच सहयोग, समुद्री सहयोग, रक्षा अभ्यास, क्षमता विकास, समुद्री

प्रौद्योगिकी सहित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग और संस्थागत अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के निरंतर विस्तार का स्वागत किया और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान तथा संवाद तंत्र को नियमित रूप से बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगामी मंत्रिस्तरीय दौरों, जिनमें इस वर्ष के अंत में होने वाली 2+2 बैठकें भी शामिल हैं, के संभावित परिणामों पर चर्चा की।

दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और साझा रणनीतिक हित के उभरते क्षेत्रों सहित उभरते क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भारत और जापान के बीच बढ़ते तालमेल पर संतोष व्यक्त किया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

रक्षा सचिव ने रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ जापान की निरंतर भागीदारी की सराहना की और भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के तहत व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। श्री कानो कोजी ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने की जापान की प्रतिबद्धता को दोहराया।

रक्षा नीति संवाद से पहले रक्षा सचिव ने जापान के रक्षा मंत्री श्री शिंजीरो कोइजुमी से मुलाकात की और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की ओर से शुभकामनाएं दीं। दोनों पक्षों ने भारत-जापान की बढ़ती विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की पुष्टि की। रक्षा सचिव ने, रक्षा मंत्री की ओर से जापान के रक्षा मंत्री को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

रक्षा सचिव ने टोक्यो में आत्मरक्षा बलों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी यात्रा की शुरुआत की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जापान के आत्मरक्षा बलों के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी।

इस यात्रा ने भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों, आपसी सम्मान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के ब्लॉकबस्टर मुकाबले का शेड्यूल जारी, इन टीमों के बीच होगी जंग

(जीएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गया है। टॉप की चार टीमों ने धमाकेदार मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में इन चार में से कोई दो टीमें ही फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हो सकेंगी। ऐसे में फुटबॉल फैंस के बीच अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है।

कब होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप में होने वाले सेमीफाइनल का पहला मुकाबला 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। वहीं, 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। चारों ही टीमें इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिससे फुटबॉल फैंस को दो हाई-वोल्टेज मैच देखने को मिलेंगे।

फ्रांस के सामने स्पेन की चुनौती

टूर्नामेंट में अब तक फ्रांस का प्रदर्शन बेहद दबदबा बनाने वाला रहा है। फ्रांसीसी टीम ने अपने पिछले मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं, जिसके कारण उन्हें इस सेमीफाइनल में जीत का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दूसरी तरफ स्पेन की टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता। स्पेन ने अपने पिछले दो नॉकआउट मैचों में पुर्तगाल और बेल्जियम जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर अंतिम-4 में जगह बनाई है। ऐसे में फ्रांस के लिए स्पेन के डिफेंस को भेदना आसान नहीं होगा।

इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच कांटे की टक्कर

फीफा विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक केवल एक बार भिड़ंत हुई है। साल 2006 के विश्व कप में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराया था। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सफर इस बार थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। टीम ने केप वर्डे, मिस्र और स्विट्जरलैंड के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। पिछले कुछ मैचों में अर्जेंटीना का खेल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।

इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना का मैच 16 जुलाई भारतीय समयानुसार (कल) रात 12:30 बजे अटलांटा स्टेडियम में खेला जाने वाला है। विश्व कप इतिहास में दोनों देशों के बीच काफी पुराना इतिहास रहा है। दोनों टीमें अब तक विश्व कप में 5 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 3 बार इंग्लैंड ने और 2 बार अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की है।

मुस्लिम फिल्ममेकर ने रचाई हिंदू लड़की से शादी, तलाक के बाद फिर उसी से कर बैठे मोहब्बत

(जीएनएस)। अपनी फिल्मों के जरिए इश्क का नया पाठ सिखाने वाले 'रॉकस्टार' फेम डायरेक्टर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी है, लोग उन्हें आने वाले जीवन के लिए दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं, हालांकि दोनों शादी कब करेंगे इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है।

लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इदा के अब्बाजान इम्तियाज अली की शादी की, जो वाकई में किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। इम्तियाज अली ने केवल एक ही लड़की से प्यार किया और बेइंतहा किया। मालूम हो कि इम्तियाज अली का दिल हिंदू लड़की प्रीति पर आ गया था, दोनों की मुलाकात हुई और फिर इन्हें लगा कि ये हमसफर बन सकते हैं।

दोनों ने अलग-अलग धर्म होने के बावजूद साल 1995 में शादी रचा ली, दोनों एक-दूसरे के सपोर्टिंग सिस्टम बने रहें, कहते हैं कि इम्तियाज के संघर्ष के दिनों में प्रीति ने उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया, दोनों को शादी से एक बेटी इदा है लेकिन जैसे-जैसे इम्तियाज तरक्की के सीढ़ियां चढ़ते गए, वो परिवार और प्रीति से दूर होते चले गए और फिर एक दिन खबर आई की दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है और साल 2012 में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए।

2012 से लेकर 2020 तक अली और प्रिया अलग-अलग रहे

तब इदा अमेरिका में पढ़ रही थी, दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया था लेकिन दोनों बेटी की वजह से हमेशा साथ रहे। प्रीति भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ शार्ट फिल्में भी बनाई हैं। साल 2012 से लेकर 2020 तक अली और प्रिया अलग-अलग रहे लेकिन फिर आया कोरोना काल, जिसने ना जाने कितनी जिंदगियाँ खत्म कर दीं लेकिन इम्तियाज की लाइफ में इसने बड़ा बदलाव किया।

साल 2020 में इम्तियाज अली और प्रीति फिर रहने लगे साथ

कहते हैं ना कि वक्त बदल जाए लेकिन जज्बात नहीं बदलते, वही हुआ इम्तियाज अली और प्रिया के साथ, साल 2020 में दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया, अली ने अपनी बेटी को भी अमेरिका से बुला लिया और फिर वे पूरा परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रहने लगा और एक तरह से फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह इम्तियाज अली और प्रिया की लाइफ फिर से सेट हो गई और अब बहुत जल्द उनकी फैमिली में एक नया सदस्य दामाद के रूप में एड होने जा रहा है, खास बात ये है कि अली का दामाद भी हिंदू है।

इम्तियाज अली ने लीक से हटकर बनाईं लोकप्रिय फिल्में

मालूम हो कि 16 जून 1971 को जमशेदपुर में जन्मे इम्तियाज अली ने सोचा ना था (2005), जब वी मेट (2007) और लव आज कल (2009), और नाटक रॉकस्टार (2011), हाइवे (2014), तमाशा (2015), जब हैरी मेट सेजल (2017), अमर सिंह चमकीला (2024), और मैं वापस आऊंगा (2026) जैसी शानदार फिल्में लोगों को दी हैं, जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं।

छोरियों ने लिया छोरों का बदला, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रनों से चटाई धूल

(जीएनएस)। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए इंग्लैंड की महिला टीम को धूल चटाने का काम किया है। मेजबान टीम को उनके घर में जाकर भारतीय टीम ने बड़े अंतर से पराजित कर दिया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने धमाका कर दिया। 142 सालों में पहली बार लॉर्ड्स में महिला टेस्ट हुआ, इसे जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया।

हाल ही में टी20 सीरीज में पुरुष टीम को इंग्लैंड ने क्लीन स्वीप किया था। उसका बदला महिला क्रिकेट टीम ने ले लिया है। भारतीय टीम ने इस मैच में 270 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। चौथे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 186 रनों के कुल स्कोर पर आउट कर दिया।

बड़े लक्ष्य के जवाब में बिखरी इंग्लिश टीम

भारतीय टीम से इंग्लैंड को 457 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई और घरेलू दर्शकों के सामने 186 रनों के स्कोर पर आउट होकर मैच हार गई। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में सोफी एक्लेस्टन और एमी जोंस ने अर्धशतकीय पारियां खेली। भारत के लिए दूसरी पारी के दौरान स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

इंग्लैंड ने जीता था टॉस

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने धाकड़ अंदाज में खेलते हुए इंग्लिश गेंदबाजों का धुआं निकाल दिया। मंधाना ने 83, हरमन ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रनों की पारियां खेली। पहली पारी में भारतीय ने 285 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया।

क्रांति गौड़ की तूफानी गेंदबाजी

जवाब में खेलते हुए इंग्लैंड की पहली पारी महज 170 रनों के मामूली स्कोर पर ही सिमट गई। एमी जोंस के बल्ले से फिफ्टी आई लेकिन क्रांति गौड़ ने ऐतिहासिक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम करते हुए तहलका मचा दिया और लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करा लिया।

यास्तिका भाटिया का शतक

इसके बाद दूसरी पारी में भारत के लिए यास्तिका भाटिया ने तूफान मचाते हुए शतक जमा डाला। वह 113 रनों की पारी खेलकर आउट हुईं। स्मृति मंधाना का बल्ला इस बार भी चला। वह 70 और ऋचा घोष 50 रन बनाने में सफल रहीं। भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी और फिर इंग्लैंड को 186 पर आउट कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com•garvigujarat2007@yahoo.com•Website : www.garvigujarat.co.in

भिलाई के साफ्टवेयर इंजीनियर ने सीतापुर की लिव इन पार्टनर की गुड़गांव में हत्या की, फिर ट्रेन से कटकर दी जान

(जीएनएस)।

भिलाई। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में रविवार को हत्या के बाद आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। भिलाई निवासी एक साफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित रूप से अपनी प्रेमिका की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी और इसके बाद गढ़ी हरसरु रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अभी राजफाश नहीं हुआ है। सेक्टर-56 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृत युवक की पहचान श्रेष्ठ मलिक (25) के रूप में हुई है। वह भिलाई की विश्व बैंक कालोनी का निवासी था और गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। वह पिछले एक वर्ष से सेक्टर-55 स्थित एक अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। मृत युवती की पहचान इशारा अयूबी (25) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की रहने वाली थीं और उसी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थीं।

जांच में सामने आया है कि दोनों पिछले कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थे। इशारा तीन दिन पहले ही सेक्टर-57 स्थित पीजी छोड़कर श्रेष्ठ के साथ लिव-इन में रहने आई थीं। स्वजन के अनुसार, शनिवार से इशारा का मोबाइल फोन बंद था। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस श्रेष्ठ के अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर बेड पर इशारा का रक्तरंजित शव मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान थे और कमरे से खून से सना चाकू भी बरामद किया गया।

रेलवे ट्रैक पर मिला श्रेष्ठ का शव

उधर, शनिवार शाम गढ़ी हरसरु के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। जीआरपी ने उसकी पहचान श्रेष्ठ मलिक के रूप में कर स्वजन को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद जब परिवार घर लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी सेक्टर-56 थाना पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया और युवती की हत्या की जानकारी दी। श्रेष्ठ के पिता दीपक मलिक ने पुलिस को बताया कि उन्हें बेटे के रिश्ते की जानकारी नहीं थी।

फोन चैट और काल डिटेल खंगालेगी पुलिस

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। अब दोनों के मोबाइल फोन, काल डिटेल रिकार्ड, व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट मीडिया गतिविधियों की जांच की जाएगी। साथ ही कंपनी के सहकर्मियों, दोस्तों और अपार्टमेंट के अन्य निवासियों से पूछताछ कर घटना की वास्तविक वजह का पता लगाया जा रहा है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का टोल चार्ज, बनाने में कितने करोड़ का आया खर्च, जानें पूरी बात

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसका शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच सफर का समय करीब तीन घंटे से घटकर 40 मिनट रह जाने की उम्मीद है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग तीन घंटे से घटकर 40 मिनट रह जाने की उम्मीद है। इसे बनाने में कितनी लागत आई, इसमें टोल चार्ज कितना होगा, इसे किस कंपनी ने बनाया? आइए, यहां इन सवालों के जवाब जानते हैं।

एक्सप्रेस-वे को बनाने में आया कितना खर्च?

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस छह-लेन वाले एक्सप्रेस-वे को बनाने में 4,200

करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें तीन इंटरचेंज, दो फ्लाईओवर, एक रोड ओवरब्रिज (ROB), चार बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 12 गाड़ियों के लिए अंडरपास, 14 हल्के वाहनों के लिए अंडरपास, 11 पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास और रास्ते में दो जगह सुविधाएं शामिल हैं।

एक्सप्रेस-वे पर कितना देना होगा टोल?

इस एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही मौजूदा रूट पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। एक्सप्रेस-वे पर दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। यह पाबंदी सिक्स-लेन कॉरिडोर के एक्सेस-कंट्रोल्ड डिजाइन का हिस्सा है। NHAI ने एक तरफ के लिए 275 रुपये और 24 घंटे के अंदर वापसी के लिए 415 रुपये टोल तय किया है।

सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम?

इस एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) भी लगाया गया है। इसमें 21 वेरिएबल मैसेज साइन (VMS), 63 PTZ कैमरे, 27 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम (VIDS), 62 इमरजेंसी कॉल बॉक्स, छह स्पीड मापने वाले रडार और नौ स्टैटिक वे-ब्रिज शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी पर बना चंदवारा पुल उद्घाटन से पहले दरकने लगा

किस कंपनी ने बनाया है?

63 किमी लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (NE-6) का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इन्फ्राटेक लिमिटेड ने किया है। 4,200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 40 मिनट रह गया है।

लखनऊ-हरदोई के बीच एक्सप्रेस-वे का प्लान

एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन किया जाएगा, वह है हरदोई और लखनऊ के बीच NH 731 के पैकेज चार का फोर-लेन निर्माण। 541 करोड़ रुपये की लागत से बना यह 32 किमी लंबा हाईवे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। यात्रियों और सामान की आवाजाही को आसान करेगा।

विपक्ष को राम मंदिर मामले में सवाल करने का हक नहीं : उ.प्र. के कबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने प्रतापगढ़ पर किया प्रहार

कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने प्रतापगढ़ में कहा कि राम मंदिर प्रकरण पर विपक्ष का सवाल उठाना हिंदुओं की आस्था कमजोर करने की साजिश है।

(जीएनएस)।

प्रतापगढ़। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि राम मंदिर में हुए प्रकरण को लेकर हिंदुओं की आस्था कमजोर करने की साजिश हो रही है। कुछ नकली सनातनी और मारीच चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। यह वही लोग हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, सरयू के पानी को खून से लाल कर दिया था। प्रभु राम

को काल्पनिक कहा था। इनकी बातों का जवाब देना भी हम जरूरी नहीं समझते।

पौधारोपण अभियान में कैबिनेट मंत्री हुए शामिल

प्रतापगढ़ में एक पौधा मां के नाम अभियान के प्रभारी के रूप में रविवार को आए मंत्री ने तौंकलपुर रानीगंज में बरगद के पौधा लगाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस प्रकरण पर सख्त हैं। एसआइटी जांच कर रही है। कई आरोपित जेल भेज चुके हैं। ऐसे में विपक्ष को राग अलापने की जरूरत क्या है।

मंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की

खाद्य रसद मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने पौधे लगाने का अभियान चलाकर इस धरती को प्रदूषण के महासंकट से उबारने का काम किया है। पौधारोपण करने के बाद मंत्री ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री योगी का जनता दर्शनः अवैध कब्जेदारों और अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनीं फरियादियों की शिकायतें। अवैध कब्जेदारों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बिल्डर धोखाधड़ी मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात कर उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर

सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये। पीड़ितों ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को ससमय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाए।

गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी 'जनता दर्शन' के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची। पीड़ितों ने बताया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट कई लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है।

इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला; बीए प्रवेश परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवालों पर मिलेंगे पूरे अंक

स्नातक प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में गणित विषय से संबंधित 10 सवाल पूछ लिए गए थे.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी सैनी ने एक बार फिर छात्र हितों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाई है. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक प्रवेश परीक्षा 2026-27 के अंतर्गत बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस (पाठ्यक्रम से बाहर) के प्रश्नों के मामले में कुलपति ने बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बी.ए. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को गणित विषय के उन सभी 10 प्रश्नों के पूरे अंक (फुल मार्क्स) समान रूप से प्रदान किए जाएंगे.

क्या था पूरा मामला

हाल ही में संपन्न हुई बी.ए. स्नातक प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में गणित विषय से संबंधित 10 सवाल पूछ लिए गए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद जब अभ्यर्थियों द्वारा यह बात सामने लाई गई कि विश्वविद्यालय

द्वारा पूर्व निर्धारित और प्रदान किए गए आधिकारिक सिलेबस (पाठ्यक्रम) में गणित विषय का कहीं कोई उल्लेख नहीं था तो असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई थी. गैर गणित पृष्ठभूमि (विशेषकर आर्ट्स और 'मेनिटीज) के छात्रों को लग रहा था कि इन अनपेक्षित 10 प्रश्नों के कारण उनकी मेरिट पर विपरीत असर पड़ेगा और वे प्रवेश की दौड़ में पिछड़ सकते हैं.

कुलपति का त्वरित संज्ञान और राहत

जैसे ही यह मामला कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के संज्ञान में आया, उन्होंने बिना किसी देरी के छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए इस पर त्वरित निर्णय लिया. कुलपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर हुई गलती का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना पड़ेगा. उन्होंने पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए गणित के सभी प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को बोनस के रूप में देने के निर्देश जारी कर दिए.

कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि "लखनऊ विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है. प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न आना एक तकनीकी त्रुटि थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया है. किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी रहेगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन के इस त्वरित फैसले से बी.ए. प्रवेश परीक्षा में बैठे हजारों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने बड़ी राहत की सांस ली है. प्रवेश समन्वयक प्रो अनित्य गौरव ने बताया कि कुलपति के आदेशानुसार परीक्षा के परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में इस संशोधन को तत्काल प्रभावी कर दिया गया है, ताकि मेरिट सूची पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिहीन बने.

लखनऊः घर में पेट्रोल में कर रहे थे मिलावट, 4 लोग दबोचे गए, हजारों लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर जब्त

मलिहाबाद में संन्यासी बाग इलाके में रविवार सुबह पुलिस, आपूर्ति विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापेमारी की। टीम ने अवैध रूप से स्टोर हजारों लीटर पेट्रोल से भरा एचपी कंपनी का टैंकर जब्त किया।।

(जीएनएस)।

मलिहाबाद : मलिहाबाद में संन्यासी बाग इलाके में रविवार सुबह पुलिस, आपूर्ति विभाग और आबकारी

विभाग की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापेमारी की। टीम ने अवैध रूप से स्टोर हजारों लीटर पेट्रोल से भरा एचपी कंपनी का टैंकर जब्त किया। साथ ही, मकान में रखे गैलनों से मिश्रित पेट्रोल और सॉल्वेंट केमिकल बरामद किया।

इन केमिकल की मिलावट कर पेट्रोल बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से चार लोगों को पकड़ा है। एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि आरोपित पेट्रोल और डीजल के टैंकरों में पाइप डालकर लगभग 200 लीटर फ्यूल निकाल लेते थे। इसके बाद, निकाली गई मात्रा को पूरा करने के लिए उसमें सॉल्वेंट केमिकल मिला दिया करते थे।

पेट्रोल पंप से सूचना के आधार पर कार्रवाई

संयुक्त टीम ने मौके से संन्यासी बाग निवासी अनिल प्रजापति, कोकोरी निवासी अभिषेक, हरदोई निवासी राम तीरथ और उन्नाव निवासी धीरज को पकड़ा है। यह कार्रवाई विधानसभा मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर की गई है। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और केमिकल के सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं। लैब रिपोर्ट के स्पष्ट होगा कि ईंधन में किस स्तर पर और कौन से रसायनों की मिलावट हो रही थी। संदिग्धों से पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई होगी।

75 रुपये लीटर बेचते थे पेट्रोल

एडीसीपी क्राइम के मुताबिक बरामद एचपी के टैकर का चालक रामतीर्थ है। उसने बताया कि वह अमौसी स्थित तेल डिपो से पेट्रोल और डीजल लोड कर निर्धारित पेट्रोल पप के लिए निकला था। रास्ते मे टैकर से पेट्रोल निकालकर अनिल कुमार को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता था। भवन स्वामी अनिल कुमार ने बताया कि वह विभिन्न टैंकर चालकों से साठगाठ कर पेट्रोल-डीजल खरीदता था। उसमे साल्वेट मिलाकर स्थानीय ग्राहकों को अधिक कीमत पर बेचता था। इस काम में अभिषेक राजपूत और धीरज सिह उसका सहयोग करते थे। मौके से एचपी का टैकर, मारुति वैन, 7.750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, 1,150 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल, लगभग 3,200 लीटर सॉल्वेट, मास्टर की. 15 लीटर का मापक व अन्य उपकरण मिले है।

मिलावटी फ्यूल से वाहनों में खराबी का शक

एडीसीपी क्राइम के मुताबिक हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के सबंध में कई दावे किए जा रहे है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया यह आशका सामने आई कि कहीं वाहनों में आ रही तकनीकी समस्याओं के पीछे पेट्रोल और डीजल में अवैध अपमिश्रण, ईंधन की चोरी और अवैध

बीएफएसआई सेक्टर के लिए डिजिटल जोखिम रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण जारी

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन), वित्त क्षेत्र में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसईआरटी-एफआईएन) और एसआईएसए के साथ मिलकर आज बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) तथा भुगतान प्रणाली के लिए डिजिटल जोखिम रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों, नियामकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और डिजिटल भुगतान को प्रभावित करने वाले खतरों का व्यापक आकलन प्रदान करती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस. कृष्णन ने रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, ह्लजैसे-जैसे साइबर खतरे अधिक जटिल होते जा रहे हैं, डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों और उद्योग के बीच विश्वसनीय साझेदारी आवश्यक है। डिजिटल जोखिम रिपोर्ट सीईआरटी-आईए, सीएसईआरटी-एफआईएन और एसआईएसए के बीच एक सार्थक सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। यह साझेदारी दशार्ती है कि भारत में विकसित विशेषज्ञता हमारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा ज्ञान को आगे बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे सकती है।'

यह रिपोर्ट व्यापक डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स (डीएफआईआर) अनुसंधान, सीईआरटी-आईएन और सीएसईआरटी-एफआईएन के अवलोकनों के अनुरूप विश्लेषण और एडवर्सरियल एआई पर किए गए अनुसंधान पर आधारित है। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि पिछले वर्ष के संस्करण में की गई सात भविष्यवाणियों में से छह पूर्णतः साकार हो चुकी हैं। यह तीव्र प्रगति दशार्ती है कि किसी खतरे के उभरने और उसके प्रचालनगत उपयोग के बीच का समय कैसे कम होता जा रहा है, जो अक्सर वर्षों से घटकर महीनों या हफ्तों तक सीमित हो जाता है।

पहले उभरते या छिटपुट माने जाने वाले खतरे- जिनमें सोशल इंजीनियरिंग, क्रेडेंशियल चोरी, सप्लाई-चेन में सेंधमारी और क्लाउड का दुरुपयोग शामिल हैं- अब स्थापित आक्रमण विधियां बन

गए हैं। इसका परिणाम यह है कि अब सबसे विनाशकारी हमले पारंपरिक घुसपैठों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। वे वैध सत्रों, स्वीकृत भुगतानों, कार्य प्रवाह की गड़बड़ियों या सामान्य उपयोगकर्ता व्यवहार के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें नुकसान हो चुकने तक वास्तविक गतिविधि से अलग करना मुश्किल होता है।

एसआईएसए के संस्थापक और सीईओ दर्शन शांतमूर्ति ने कहा, "नवाचार और शोषण के बीच का अंतर नाटकीय रूप से कम हो गया है। इस एक बदलाव ने हमारे उद्योग को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में सब कुछ बदल दिया है। बीएफएसआई उद्योग भरोसे पर टिका है- यह भरोसा कि लेन-देन वास्तविक है कि इसे प्रोसेस करने वाले सिस्टम इच्छानुसार काम कर रहे हैं और पैसा एक-दूसरे पर निर्भर संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रूप से आगे बढ़ेगा। जब यह भरोसा कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव कभी भी किसी एक उल्लंघन या किसी एक फर्म तक सीमित नहीं रहता, यह ग्राहकों, भागीदारों, बाजारों और पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा अब व्यवसाय के हाशिये पर एक तकनीकी नियंत्रण कार्य के रूप में नहीं रह सकती। इसे संस्थानों के विकास, नवाचार और नेतृत्व के केंद्र में होना होगा। फोरेंसिक में हमारे काम ने हमें एक सरल सच्चाई सिखाई हैः हर उल्लंघन एक सबक छोड़ जाता है और अगर हम तेजी से सीखने को तैयार हैं, तो वे सबक व्यवधान को दूरदर्शिता में बदल सकते हैं।"

रिपोर्ट में वित्तीय संस्थानों के सामने विद्यमान प्रमुख जोखिमों में से एक के रूप में एआई विषमता की पहचान की गई है। जिन कार्यों के लिए कभी विशेषज्ञ टीमों, पर्याप्त संसाधनों और कई सप्ताह के प्रयास की आवश्यकता होती थी, उन्हें अब अपेक्षाकृत कम संसाधनों वाले हमलावर भी मशीन की गति से कर सकते हैं। इससे आक्रमणकारी क्षमताएं उन रक्षात्मक और नियामक तंत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही हैं जिन्हें इन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कहा, ह्लबीएफएसआई उद्योग के लिए डिजिटल खतरे की रिपोर्ट पर लगातार दूसरे वर्ष एसआईएसए के साथ सहयोग करके हमें खुशी हो रही है। जैसे-जैसे भारत का वित्तीय तंत्र अधिक इंटरकनेक्टेड, वास्तविक समय पर आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित होता जा रहा है, साइबर सुरक्षा को संस्थानों, नियामकों और व्यापक डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला के बीच एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह रिपोर्ट आवधिक सुरक्षा उपायों से आगे बढ़कर निरंतर जोखिम मूल्यांकन, समन्वित प्रतिक्रिया और मजबूत सूचना साझाकरण की आवश्यकता रेखांकित करती है।

अयोध्या में भदरसा का नाम बदलकर हुआ 'भरत नगर', सीएम योगी ने वापस दिलाई भरत की तपोभूमि की ऐतिहासिक पहचान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर 'भरत नगर' कर दिया है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत ...और पढ़ें

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर 'भरत नगर' कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद से श्रद्धालुओं में उत्साह है। उनकी सनातन आस्था को सम्मान मिलने से गदगद हैं।

भदरसा का संबंध सीधे भगवान श्रीराम के अनुज भरत की तपोभूमि नंदीग्राम (वर्तमान भरत कुंड) से माना जाता है और इसी ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।

भरत जी ने नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीते हुए 14 वर्षों तक संभाली अयोध्या की बागडोर

जब भगवान श्रीराम चौदह वर्ष के वनवास पर गए, तब उनके अनुज भरत ने अयोध्या का राजसिंहासन स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने चित्रकूट जाकर श्रीराम से वापस लौटने का आग्रह किया,

लेकिन प्रभु श्रीराम ने पितृ आज्ञा के कारण लौटने से मना कर दिया। तब भरत जी उनकी चरण-पादुका (खड़ाऊं) लेकर वापस लौट आए थे और अयोध्या की राजसी सुविधाओं से दूर नंदीग्राम में

भरत जी ने भगवान राम की खड़ाऊं को राजसिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं 14 वर्षों तक तपस्वी जीवन जीते हुए वहीं से राज्य का संचालन किया। यही स्थान आज भरत कुंड के नाम से प्रसिद्ध है और भरत नगर इसी पवित्र क्षेत्र के निकट स्थित है। सदियों से श्रद्धालु इस पूरे क्षेत्र को भरत जी की तपोभूमि के रूप में पूजते आ रहे हैं।

भाषाई बदलावों के कारण 'भदरसा' नाम प्रचलन में आने की है मान्यता

स्थानीय परंपराओं और भाषाई मान्यताओं के अनुसार, 'भदरसा' कोई मूल नाम नहीं था, बल्कि यह समय के साथ बदला हुआ रूप माना जाता है। कहा जाता है कि रामायण काल में यह क्षेत्र भरत जी की तपोभूमि का हिस्सा था।

लोक मान्यता है कि उस समय इस स्थान को 'भरत-दशा', 'भरत-वास' अथवा 'भरत-स्थान' जैसे नामों से जाना जाता था। समय के साथ स्थानीय बोलचाल और भाषाई परिवर्तनों के कारण 'भरत' शब्द 'भदर' तथा 'दशा' या 'वास' का रूप बदलकर 'सा' हो गया, जिससे यह नाम 'भदरसा' के रूप में प्रचलित हो गया।

ओझल होने लगा था भरत जी से सीधा भाषाई संबंध

जानकारी के अनुसार, मध्यकाल और नवाबी शासन के दौरान कई प्राचीन स्थानों के नाम प्रशासनिक अभिलेखों में बदल गए या उनके मूल स्वरूप से अलग रूप प्रचलन में आ गए। इसी काल में 'भदरसा' नाम सरकारी दस्तावेजों में स्थापित हो गया, जिससे इसका मूल सनातन इतिहास और भरत जी से सीधा भाषाई संबंध ओझल सा होने लगा था।

इसके धार्मिक और सनातन महत्व को देखते हुए जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदरसा का नाम भरत नगर करने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया।

धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा

योगी सरकार लगातार उन स्थलों की पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिनका संबंध भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से रहा है। इसी क्रम में 'भदरसा' का 'भरत नगर' नाम परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की पौराणिक और धार्मिक पहचान को और अधिक मजबूत करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस जगह को सीधे भरत जी के त्याग, भाईचारे और मर्यादा की मिसाल के रूप में याद रख सकें। सरकार द्वारा अब इस पूरे 'भरत नगर' और 'भरत कुंड' क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सुरक्षित जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले शहरों की ओरः एमओएचयूए ने भारत के सभी शहरों में 'कैच द रेन' अभियान तेज किया

'कैच द रेन' अभियान में जुटे 900 से अधिक यूएलबी सक्रिय; 1.21 लाख एकड़ जल निकाय तथा 12,750 एकड़ हरित क्षेत्र अधिक सक्रिय बनाए जा रहे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री के "कैच द रेन झ जहाँ वर्षा हो, जब वर्षा हो" अभियान की गति बनाए रखने के आ'न के अनुरूप, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), अमृत 2.0 के अंतर्गत भारत के सभी शहरों में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा जल निकायों के पुनर्जीवन से संबंधित विभिन्न पहलों के माध्यम से इस राष्ट्रव्यापी अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहा है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत देशभर के शहर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा दीर्घकालिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलता को मजबूत कर रहे हैं। इस अभियान में 27 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 900 शहरी स्थानीय निकायों ने सक्रिय भागीदारी की है।

जल शक्ति अभियानझजन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के साथ समन्वय करते हुए, 79 नगर निगमों में 1,99,278 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है, जबकि 738 शहरी स्थानीय निकायों में 73,036 पुनर्भरण संरचनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये प्रयास शहरी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

इन प्रयासों को और मजबूती प्रदान करते हुए, अमृत 2.0 के

अंतर्गत उथले जलभृत प्रबंधन (एसएएम) कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक जलभृत मानचित्रण तथा लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों में उल्लेखनीय एवं ठोस परिणाम दे रहा है। बर्दवान (पश्चिम बंगाल) और विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) में इंजेक्शन बोरवेल से युक्त पुनर्भरण गड्ढों के माध्यम से वर्षा जल को गहरे जलदायी स्तरों तक पहुँचाया जा रहा है। ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में भंडारण सुविधाओं सहित छत आधारित वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ जल संरक्षण के साथ-साथ भूजल पुनर्भरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, कोरबा (छत्तीसगढ़) और वारंगल (तेलंगाना) में मानसून से पूर्व ही पुनर्भरण संरचनाओं को संचालित कर दिया गया है, जिससे मौसमी वर्षा जल का प्रभावी ढंग से संचयन एवं उपयोग जलदायी स्तरों के पुनर्भरण के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान तथा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इंजेक्शन बोरवेल सहित निर्मित पुनर्भरण गड्ढे (रिचार्ज पिट्स)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा तेलंगाना के वारंगल में मानसून से पूर्व निमार्णाधीन भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ।

ईटानगर में छत आधारित वर्षा जल संचयन हेतु भंडारण टैंक सुविधा सहित निर्मित पुनर्भरण गड्ढा (रिचार्ज पिट)।

अमृत 2.0 के जल निकाय पुनर्जीवन (डब्ल्यूबीआर) घटक के अंतर्गत लगभग 1.21 लाख एकड़ क्षेत्र में जल निकायों को अधिक मजबूत किया जा रहा है, ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हो, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिले तथा शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रति लचीलापन सुदृढ़ हो। इन कार्यों में गाद हटाना, निकायों के इनलेट एवं आउटलेट में सुधार, तट संरक्षण, भूदृश्य विकास तथा जैव विविधता संवर्धन जैसे उपाय शामिल हैं।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में, शहरी भारत में 18,00 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पार्कों एवं हरित क्षेत्र की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। ये परियोजनाएँ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने, भूजल पुनर्भरण में सहयोग करने, शहरी ताप तनाव को कम करने तथा नागरिकों के लिए सुलभ एवं जीवंत सार्वजनिक स्थलों का सृजन कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इन पहलों के माध्यम से एमओएचयूए "कैच द रेन झ जहाँ वर्षा हो, जब वर्षा हो" की कल्पना को साकार करने की दिशा में योगदान दे रहा है।

"आज बचाई गई हर बूंद, आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है।"

'पीएम मोदी की बात सुनते हैं पुतिन...', पोलैंड ने रूस-यूक्रेन जंग में भारत के रोल को बताया अहम

पोलैंड के विदेश मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी व्लादिस्लाव टेओफिल बाटोर्शेव्स्की ने भारत की रूस-यूक्रेन युद्ध में भूमिका की सराहना की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन ध्यान देते हैं और भारत शांति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है.

व्लादिस्लाव टेओफिल बाटोर्शेव्स्की (पोलैंड के विदेश मंत्रालय के स्टेट सचिव) ने भारत की भूमिका की सराहना की हैव्लादिस्लाव टेओफिल बाटोर्शेव्स्की (पोलैंड के विदेश मंत्रालय के स्टेट सचिव) ने भारत की भूमिका की सराहना की है

पोलैंड के विदेश मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी व्लादिस्लाव टेओफिल बाटोर्शेव्स्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ध्यान देते हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत की भूमिका बेहद अहम है और शांति की दिशा में उसके प्रयास

महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

बाटोर्शेव्स्की ने कहा, "भारत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शक्ति है. राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं. हालांकि समस्या यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह तय कर लिया है कि यूक्रेन पर पूरा नियंत्रण ही एकमात्र समाधान है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है." उन्होंने कहा कि युद्ध के और अधिक बढ़ने के पक्ष में कोई भी देश नहीं है. भारत ही नहीं, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी तनाव बढ़ाने के खिलाफ हैं. उनके अनुसार, जब ऐसे देश शांति और संयम की बात करते हैं जिन्हें रूस विरोधी नहीं माना जाता, तो उनका संदेश अधिक प्रभावशाली होता है.

पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव ने कहा कि भारत ने लगातार बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है. यही वजह है कि भारत की बात रूस भी गंभीरता से सुनता है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, जब दुनिया लंबे समय से जारी इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान चाहती है, भारत जैसे देशों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता युद्ध को और फैलने से रोकना होनी चाहिए. भारत, चीन और अन्य प्रभावशाली देशों की अपील से संघर्ष को नियंत्रित करने और बातचीत का रास्ता निकालने में मदद मिल सकती है. बाटोर्शेव्स्की ने दोहराया कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है और वैश्विक समुदाय भी भारत से सकारात्मक योगदान की उम्मीद कर रहा है.

धनबाद में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की मध्यस्थता से लंबित औद्योगिक विवादों का समाधान, श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए 55 लाख रुपये से अधिक की राहत सुनिश्चित

(जीएनएस)।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) (सीएलसी (सी)) का क्षेत्रीय तंत्र मध्यस्थता और विवादों के समाधान के माध्यम से औद्योगिक सद्भाव को मजबूत करने और श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धनबाद में कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के तहत, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-क्क धनबाद के कार्यालयों ने तीन लंबित औद्योगिक विवादों को सफलतापूर्वक हल किया और सेवानिवृत्त श्रमिकों तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 55 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की। लंबित मामलों का निपटारा समय पर न्याय सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और संवाद एवं आम सहमति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता हैं।

बीसीसीएल समझौते से मृत श्रमिक के आश्रितों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित

धनबाद के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-क ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की बुर्रागढ़ कोलियरी के एक मृत श्रमिक के आश्रितों के लिए मौद्रिक मुआवजे से संबंधित औद्योगिक विवाद के समाधान में सहायता प्रदान की। कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के संयुक्त महासचिव द्वारा उठाया गया यह विवाद प्रबंधन और श्रमिक संघ के बीच मध्यस्थता के बाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

1 जुलाई 2026 को एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर के तहत आश्रित को 60 वर्ष की आयु तक मासिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। लगभग 30 लाख रुपये के इस समझौते से शोक संतप्त परिवार को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और समय पर सामाजिक सुरक्षा सहायता सुनिश्चित होगी।

मध्यस्थता समझौते से एफसीआईएल के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिली

धनबाद के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-क्क ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों पर ब्याज के विलंबित भुगतान से संबंधित लंबित विवाद का निपटारा किया गया।

मध्यस्थता के बाद, 7 जुलाई 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत एफसीआईएल प्रबंधन सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर अनुग्रह राशि और अवकाश नकदीकरण के वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने पर सहमत हुआ। लगभग 14 लाख रुपये के इस समझौते से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिली है।

पूरी कार्यवाही के दौरान, सेवानिवृत्ति लाभों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने और श्रमिकों के वैध अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियोक्ताओं के वैधानिक दायित्व पर जोर दिया गया। प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह की देरी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे।

आरएलसी (सी) धनबाद ने मृतक ईसीएल कर्मचारी के आश्रितों के लिए निपटान की सुविधा प्रदान की

धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के एक मृत कर्मचारी के आश्रित के लिए मौद्रिक मुआवजे से संबंधित विवाद का समधान किया।

प्रबंधन और श्रमिक संघ के बीच निरंतर मध्यस्थता-समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 3 जुलाई 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लगभग 11 लाख रुपये के इस समझौते से आश्रित को मासिक मुआवजा और शोक संतप्त परिवार को समय पर वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा सहायता सुनिश्चित होती है।

मध्यस्थता के दौरान, ईसीएल प्रबंधन को श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता प्रदान करने से संबंधित अपने वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यवाही ने रचनात्मक संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया।

सीएलसी (सी) तंत्र नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, श्रम कानूनों का अनुपालन, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विश्वास और सहयोग को जारी रखता है।

ये पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की श्रम कल्याण के उद्देश्यों को मूर्त परिणामों में बदलने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं, जिसके तहत प्रभावी मध्यस्थता और सामाजिक संवाद के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों को समय पर न्याय, वित्तीय सुरक्षा और वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकें।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल प्रवास पर रहेंगे, मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी के साथ होगी हाई लेवल मीटिंग

कोलकाता में उच्चस्तरीय बैठक में श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं पर करेंगे चर्चा

प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, फसल बीमा योजना, वीबी- जी राम जी, ग्रामीण सड़क और आवास योजना आदि की विस्तृत समीक्षा करेंगे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह बंगाल में जूट किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और लखपति दीदियों से सीधा संवाद भी करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13-14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस प्रवास के दौरान श्री शिवराज सिंह वहां मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी के साथ कृषि और ग्रामीण विकास पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और जूट क्षेत्र के किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 जुलाई की शाम दिल्ली से कोलकाता पहुँचेंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएँगे। रात्रिभोज के साथ होने वाली इस बैठक में खेती, किसानों की योजनाएँ, ग्रामीण सड़कों, आवास और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य नेतृत्व साथ बैठेगा।

दूसरे दिन 14 जुलाई को नए सचिवालय भवन, कोलकाता में उच्चस्तरीय बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारी तथा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी सहभागिता करेंगे। केंद्र की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईसीएआर की टीम पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, एमएसपी, विकसित भारत-जी राम जी, ग्रामीण सड़क और आवास तथा पंचायतों को मिलने वाले फंड जैसे कार्यक्रमों की स्थिति रखेगी और आगे के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

दोपहर बाद श्री शिवराज सिंह चौहान बैरकपुर स्थित आईसीएआर-सीआरआईजैफ (केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान) पहुँचेंगे। यहाँ जूट क्षेत्र के किसान और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ जुटेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान उनसे सीधे सुनेंगे कि जूट की खेती में रेटिंग, पानी, रोग-कीट, लागत और कीमत जैसी समस्याएँ जमीन पर कैसी हैं और जूट वैल्यू चेन में किसानों का हिस्सा कैसे बढ़ाया जा सकता है। संस्थान के वैज्ञानिक जूट की बेहतर किस्मों, आधुनिक रेटिंग, जल संरक्षण और प्रोसेसिंग-मार्केटिंग की आसान तकनीकों की जानकारी देंगे। साथ ही महिलाओं के समूहों को जूट आधारित उत्पाद और वैल्यू एडिशन के माध्यम से छोटे उद्यम खड़े करने के तरीके बताए जाएँगे ताकि गांवों में आय और रोजगार दोनों बढ़ें।

केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दो दिन की इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष स्तर पर और जूट बेल्ट के किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संवाद के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार यह साफ संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास उसके राजनीतिक और नीतिगत एजेंडे के केंद्र में हैं।

भारत एआई-आधारित प्रशासनिक सुधारों के साथ शासन में परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा हैः डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शिलांग में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई-गवर्नेंस सुधारों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

एआई-सक्षम शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना देश के अगले सुधार एजेंडे को आकार देंगेः डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगली पीढ़ी के शासन सुधारों को गति देने के लिए "सुधार एक्सप्रेस" का आ'न कियाः डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि एक दशक से अधिक समय से किए जा रहे अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधारों और लगभग 2,000 अप्रचलित नियमों को हटाने के बाद, भारत अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई-गवर्नेंस सुधारों के माध्यम से शासन परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान "सुधार एक्सप्रेस" के आ'न का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य के सुधारों में एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवा प्लेटफार्मों को एकीकृत करना आवश्यक है ताकि, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन प्रणाली का विकास किया जा सके जो वर्ष 2047 के विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज शिलांग में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अगली पीढ़ी के प्रशासनिक एवं ई-गवर्नेंस सुधारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनरैड के. संगमा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, मेघालय के मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर और देश भर से प्रतिनिधि उपस्थित थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधारों को देश के विकास का आधार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल सशक्तिकरण और परिणामोन्मुखी प्रशासन के सिद्धांतों के माध्यम से शासन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में नागरिकों को केंद्र में रखते हुए, नियमन से सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रगति की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन अब नई दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग मजबूत हुआ है और सफल शासन पद्धतियों को व्यापक स्तर पर साझा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शिलांग का विशेष महत्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पिछली शिलांग घोषणा की तरह, सुधार एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन भी "शिलांग घोषणा 2.0" के रूप में परिणत होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास दृष्टिकोण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगभग अस्सी बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जो पूर्वोत्तर को दी गई अभूतपूर्व प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हाल ही में 'मन की बात' में मेघालय के 'लिविंग रूट ब्रिजेस' की सराहना का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मेघालय सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास और नवोन्मेषी शासन का आदर्श बन गया है।